भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके वित्तीय तंत्र का क्रमिक विकास अत्यंत ही जटिल और संघर्षपूर्ण प्रक्रियाओं से होकर गुज़रा है जिसने हमारे महान् राष्ट्र को आज वैश्विक पटल पर एक नई और सुदृढ़ पहचान दिलाई है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारतीय धन का जो निर्दयतापूर्वक दोहन हुआ था उसके पश्चात् देश को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सर्वप्रमुख लक्ष्य बन गया था। देश की केंद्रीय बैंकिंग संस्था अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की विस्तृत सिफ़ारिशों के आधार पर पाँच करोड़ रुपये की प्रारंभिक शेयर पूँजी के साथ की गई थी जिसका मुख्य कार्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और मौद्रिक स्थिरता को अक्षुण्ण बनाए रखना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 1 जनवरी 1949 को रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसे पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में ला दिया गया। इसके उपरांत बैंकिंग सुविधाओं को दूरदराज़ के गाँवों और कस्बों तक पहुँचाने के पुनीत उद्देश्य से 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनके पास उस समय लगभग 50 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि उपलब्ध थी। इसी शृंखला में 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य प्रमुख बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वर्ष 1991 के भयंकर आर्थिक संकट के दौरान जब देश का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 1.2 अरब डॉलर के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया था तब 24 जुलाई 1991 को ऐतिहासिक उदारीकरण वैश्वीकरण और निजीकरण की नई आर्थिक नीतियाँ लागू की गईं। इन साहसिक नीतियों ने विदेशी निवेश के मार्ग की सभी बाधाओं का समूल नाश कर दिया और भारतीय बाज़ारों में अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। आधुनिक समय में सरकार ने काले धन और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने हेतु 8 नवंबर 2016 की मध्यरात्रि को विमुद्रीकरण का ऐतिहासिक और कठोर निर्णय लिया जिसके परिणामस्वरूप 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। इसके पश्चात 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया जो कि स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा और व्यापक अप्रत्यक्ष कर सुधार माना जाता है। आज के इस डिजिटल युग में भारतीय भुगतान प्रणाली ने संपूर्ण विश्व में अपना उत्कृष्ट तकनीकी लोहा मनवाया है। 11 अप्रैल 2016 को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूपीआई प्रणाली का सफल शुभारंभ किया गया था और आज प्रतिमाह लगभग 1200 करोड़ से अधिक का डिजिटल लेनदेन अत्यंत सुगमता और सुरक्षित तरीके से पूर्ण किया जा रहा है। बुनियादी ढाँचे के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत माला और सागर माला जैसी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं पर भी तीव्रता से कार्य चल रहा है। भारतीय रेलवे जो कि देश की जीवन रेखा मानी जाती है उसमें 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। आज देश भर में 100 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें पटरियों पर दौड़ रही हैं और रेलवे नेटवर्क के शत प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य पूर्णता की ओर है। दूरसंचार के क्षेत्र में भी 1 अक्टूबर 2022 को देश में 5जी इंटरनेट सेवाओं का विधिवत शुभारंभ हुआ जिससे डेटा हस्तांतरण की गति